वर्ष 18 अंक 7 जुलाई 1996 मूल्य: दो रुपये

सीटू मजदूर

सी. आइ. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सी आइ टी यू वर्किंग कमेटी की बैठक
7-9 जून, 1996

अध्यक्षीय भाषण

□ ई. बालानंदन

प्रिय साथियो,

सर्व प्रथम मैं कामरेड वी जी भास्करन नायर के देहावसान पर गहरा दु:ख व्यक्त करता हूं। वह हमारे अखिल भारतीय सचिवों में से एक तथा सी आइ टी यू की केरल राज्य समिति के सचिव थे। वह सी पी आइ (एम) की केरल राज्य समिति के सदस्य थे। उनका देहांत 28 अप्रैल को हुआ। वह कैंसर से पीड़ित थे। कामरेड भास्करन नायर ने अपना पूरा जीवन श्रमिक आंदोलन के लिये लगा दिया और वह एक समर्पित कम्युनिस्ट थे। उनके देहावसान से केरल में एक ऐसी खाई उत्पन्न हो गई है जिसे पाटना सहज नहीं होगा। आपकी ओर से मैं उन्हें आदरपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और उनके परिवार के दु:खी सदस्यों को वर्किंग कमेटी की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रेषित करता हूं।

सी आइ टी यू वर्किंग कमेटी की भिलाई बैठक के पश्चात् हमारे अनेक कार्यकर्ता तथा नेता हमें विच्छोह दे गए हैं। आईये, हम उन्हें भी अपनी भावपूरत एवं आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें।

साथियो,

हम वर्किंग कमेटी की भिलाई बैठक (2-4 नवंबर, 1995) के पश्चात् मिल रहे हैं। इस समय देश एक गम्भीर मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहले कभी भी ऐसी अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। भिलाई की बैठक में हमने नयी आर्थिक नीतियों की रचयिता कांग्रेस (इ) तथा भाजपा के नेतृत्व में काम करने वाली साम्प्रदायिक शक्तियों को परास्त करने और उभर रहीं वाम पक्षीय, जनवादी एवं धर्म निरपेक्ष शक्तियों जिनका नेतृत्व राष्ट्रीय मोर्चे तथा वाम मोर्चे द्वारा किया जा रहा था, की विजय को सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया था। नि:संदेह कांग्रेस (इ) को चुनावों में पराजय हुई है तथा उसकी शक्ति पहले से क्षीण हुई है किन्तु भाजपा के नेतृत्व वाली साम्प्रदायिक शक्तियां लोक सभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने में सफल हुई हैं और उनके द्वारा सत्ता को हस्तगत करने का प्रयास भी किया गया। इसी तर्क के आधार पर श्री वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री बन बैठे थे। देश इस समय एक दोराह पर खड़ा है। क्या देश की एकता तथा अखण्डता और इसके धर्म निरपेक्ष स्वरूप की रक्षा की जा सकती है अथवा आर एस एस की हिन्दुत्ववादी विचारधारा पर आधारित भाजपा के नेतृत्व वाली घातक साम्प्रदायिक शक्तियों के हाथों देश को खण्ड-खण्ड होने दिया जाए। भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने और श्री देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार को सत्ता में लाने के लिये राष्ट्रीय मोर्चे के घटक दलों की सहायता से वाम शक्तियों द्वारा सभी धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को लाभबंद करने के लिए किये गए प्रयास सफल रहे हैं। कांग्रेस (इ) संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन करने के लिए विवश थी। यद्यपि इन चुनावों में वाम दलों की सीट संख्या कुछ कम हुई है तथापि हम कुल मिलाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं। देश में जटिल स्थिति उत्पन्न हो गयी है; यद्यपि केन्द्र में गैर भाजपा तथा गैर कांग्रेस (इ) सरकार अस्तित्व में आ गयी है तथापि संयुक्त मोर्चे को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है और उसे भाजपा को सत्ता के गलियारों से बाहर रखने के लिए कांग्रेस(इ) का समर्थन प्राप्त करना पड़ रहा है।

इन नयी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि नयी सरकार किस प्रकार श्रमिक जनता की मांगों को पूर्ण कर सकेगी और साम्राज्यवादियों द्वारा प्रतिपादित भूमण्डलीयकृत तथा उदारीकृत अर्थ व्यवस्था के आक्रमणों से देश की आर्थिक सम्प्रभुता की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है और देश का श्रमिक वर्ग इस स्थिति का सामना कैसे

कर सकता है।

इन प्रश्नों को उत्तर देने पूर्व हमें विश्व पूंजीवाद के बढ़ते संकट पर अपने पिछले विश्लेषणों का स्मरण करते हुए वर्तमान स्थिति का अनुशीलन करना होगा। उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नयी कार्य विधि को अपनाए जाने पर भी यह संकट गहरा होता चला जा रहा है। इसी अवधि में अर्थात् 1991 के पश्चात् 1995 में अमरीकी अर्थ व्यवस्था का सबसे कम विकास हुआ है। अमरीका के वाणिज्य विभाग के अनुसार पिछले वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 2 प्रतिशत वृद्धि हुई– यह वृद्धि अत्यंत अरक्तक है क्योंकि वर्ष 1991 में अर्थ व्यवस्था एक प्रतिशत सिकुड़ गई थी। उस वर्ष सबसे अधिक आर्थिक मंदे की स्थिति आई थी। वर्ष 1994 में सकल घरेलू उत्पाद में 3.5 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों का दो तिहाई भाग उपभोक्ता व्यय का था, उसमें तीसरी तिमाही के 2.8 प्रतिशत की तुलना में चौथी तिमाही में मात्र 1.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। व्यावसायिक व्यय जिन्हें आर्थिक विकास के स्तम्भ कहा जाता है में चौथी तिमाही के समय मात्र 3.1 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। मूल रूप से इस वृद्धि को 6.2 प्रतिशत तक बताया गया। मूल कल्पना के विपरीत चौथी तिमाही में व्यापारिक घाटा भी बहुत बढ़ गया था। यद्यपि इसी मध्य निर्यातों में 11 प्रतिशत तथा आयातों में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसमें 0.1 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान था। नये घरों, अपार्टमैंटों इत्यादि का निर्माण वर्ष 1995 में 2.3 प्रतिशत कम हुआ, जो 1991 के पश्चात् सबसे बड़ा मंदा था। क्रय प्रबंधन सम्बन्धी अमरीकी संघ द्वारा तैयार कराए गए मैन्युफैक्चरिंग सूचकांक से पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग अभी भी अधोगामी रुख अपनाए हुए है। मार्च में यह 46.9 प्रतिशत था। संघ के अनुसार यह 50 प्रतिशत से कम था जो इसकी दुर्बलता को ही दर्शाता है।

'द इकानोमिस्ट' दिनांक 25–31 मई के नवीनतम अंक में विकसित पूंजीवादी देशों– सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में अधोलिखित आंकड़े दिये गए हैं। इससे हम उन देशों में अर्थ व्यवस्था की खराब स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं और हमें यह भी पता चलता है कि वहां बेरोजगारी की दर भयावह सीमा तक बढ़ रही है।

वार्षिक दर का आनुपातिक परिवर्तन

देश	सकल घरेलू उत्पाद		औद्योगिक उत्पादन	
	3 मास	1 वर्ष	3 मास	1 वर्ष
आस्ट्रेलिया	+2.0	+3.1 ति 4	−1.4	−0.3 ति 4
आस्ट्रिया	+12.8	+0.3 ति 4	−9.3	−0.6 दिसम्बर
बेलजियम	+1.6	+0.7 ति 4	+20.8	+4.3 नवंबर
ब्रिटेन	+1.5	+2.0 ति 4	+0.9	+0.6 मार्च
कैनेडा	+0.8	+0.6 ति 4	+0.6	−0.5 फरवरी
डेनमार्क	−0.2	+1.4 ति 4	3 न	−1.8 फरवरी
फ्रांस	−1.7	+0.3 ति 4	+3.4	+0.4 फरवरी
जर्मनी	−1.6	+1.0 ति 4	−4.4	−1.7 मार्च
इटली	−3.6	+2.3 ति 4	−10.6	−6.2 मार्च
जापान	+3.6	+2.2 ति 4	+2.4	−2.8 मार्च
नीदरलैंड्ज	+0.7	+1.6 ति 4	−1.2	−1.5 फरवरी
स्पेन	+1.6	+2.6 ति 4	−9.0	+0.9 फरवरी
स्वीडन	−1.4	+1.7 ति 4	−8.0	+0.6 मार्च
स्विटजरलैंड	−0.4	−0.2 ति 4	नहीं	+2.7 ति 3
अमरीका	+2.8	+1.8 ति 1	+4.3	+2.6 अप्रैल

कुछ इने गिने देशों में गहराते संकट का अनुमान बेरोजगारी के अधोलिखित आंकड़ों से हो जाता है। ये आंकड़े अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इस वर्ष दिनांक 5 मार्च को जारी एक विज्ञप्ति में दिये गए थे। उनसे पता चलता है कि निजीकरण तथा संरचनात्मक समायोजन नीति के चलते बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि ही रही है:

बेरोजगारी की दरें, 1994=1995 : इने गिने देश

देश	मार्च 1994	प्रतिशत	मार्च 1995	प्रतिशत
आस्ट्रिया	दिसंबर	8.5	जनवरी 1996	9.0
बेलजियम	दिसंबर	14.1	दिसंबर	14.5
ब्राजील	अक्टूबर	4.5	अक्टूबर	50.1
कोलम्बिया	सितंबर	7.6	सितंबर	8.7
जर्मनी	जनवरी 1995	11.1	जनवरी 1996	12.0
हांगकांग	दूसरी तिमाही	1.6	दूसरी तिमाही	2.9
जापान	दिसंबर	2.7	दिसंबर	3.2
लग्जमबर्ग	दिसंबर	2.0	दिसंबर	3.2
पुर्तगाल	तीसरी तिमाही	7.4	तीसरी तिमाही	6.9
स्वीडन	दिसंबर	7.4	दिसंबर	7.8
अमरीका	दिसंबर	5.1	दिसंबर	5.3

'वर्किंग क्लास' के जून 1996 अंक में प्रकाशित

आइ एल ओ के सांख्यिविदों ने बताया है कि इन आंकड़ों में "श्रम संचय" तथा अदृश्य बेरोजगारी के विभिन्न रूपों जैसे अवैतनिक तथा दीर्घावधि के लिऐ प्रसूति अवकाश, अर्ध बेरोजगारी, अंशकालिक रोजगार, रोजगार हिस्सेदारी, अस्थायी नियुक्ति इत्यादि को सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रौद्योगिकीय के क्षेत्र में निरंतर नये–नये आविष्कार होने के फलस्वरूप जहां स्थायी रोजगारों का अभाव हो गया है वहीं रोजगार चाहने वाली श्रम शक्ति में वृद्धि हुई है। न्यूयार्क टाइम्स द्वारा हाल ही में रिपोर्ट

प्रकाशित की गयी है कि निर्विवाद रूप से सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता बढ़ने के कारण कम्पनियों में "अस्थायी नियुक्तियों" की भरमार हो गई है। उन्होंने तकनीकी विशेषता प्राप्त रोजगार के इच्छुक लोगों को निदेश दिया है कि वे उन स्थानों पर काम करें जहां अस्थायी कार्यों के लिए उनकी आवश्यकता है। वर्ष 1990 में ऐसी केवल 44 कम्पनियां थीं ये कंपनियां सैटल में स्थित थीं, किन्तु अब उनकी संख्या लगभग 229 हो गयी है। अमरीका के श्रम विभाग ने रिपोर्ट दी है कि 1983 में देश में 6 लाख 19 हजार (6,19,000) अस्थायी रोजगार थे। वर्ष 1994 में उनकी संख्या बढ़ कर 22.50 लाख हो गई। इस पर भी बताया जा रहा है कि तकनीकी अस्थायी सेवा में वृद्धि अमरीका की रोजगार सुरक्षा के कफन में एक और कील है। परम्परागत ढंग से, ये रोजगार कोई लाभ प्रदान नहीं करते, इनसे सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती और कर्मचारियों के बांड की अवधि समाप्त होने पर ये रोजगार भी समाप्त हो जाते हैं जबकि श्रमिक ये लाभ प्राप्त करते रहे हैं और यह परंपरा रही है। इस संवृति के चलते श्रमिक संघों की गतिविधियों तथा सदस्य संख्या पर विषम प्रभाव पड़ा है। इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। केवल यही नहीं पूर्णकालिक रोजगारों में कटौती होने के कारण सप्ताह में कार्य दिवसों तथा दिन में कार्य घण्टों में भी कमी हुई है और इसके साथ-साथ वर्तमान 'स्थायी' श्रमिकों के वेतनों में भी कटौती की गयी है।

एक और बढ़ रही संवृति जिसका वर्णन मैंने भिलाई में आयोजित पिछली बैठक में भी किया था और यहां पर भी उसे दोहराना चाहता हूं, वह है अनौपचारिक अथवा असंगठित क्षेत्र का बढ़ना। आइ एल ओ की विश्व श्रम रिपोर्ट 1995 के अनुसार संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के चलते उत्पादन केन्द्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। बड़े आधुनिक उद्यमों के बंद होने से अनौपचारिक क्षेत्र जो लातिनी अमरीका में इस समय शहरी गैर कृषि रोजगार का लगभग 40 प्रतिशत, एशिया में 55 प्रतिशत तथा अफ्रीकी देशों में लगभग 70 प्रतिशत है। अकेले अमरीका में लगभग 45 प्रतिशत श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। भूमण्डलीयकृत अर्थ व्यवस्था के इस दौर में उपरोक्त सभी रुझानों का निर्यात तृतीय विश्व के देशों में किया जा रहा है।

आइ एल ओ के एक विशेषज्ञ द्वारा हाल ही में जारी किये गए एक वक्तव्य में दावा किया गया है कि इस शताब्दी के अंत तक बेरोजगारी में अत्यंत व्यापक वृद्धि हो जाएगी और इसके चलते जनता के लिए भीषण कठिनाईयां उत्पन्न हो जाएंगी। उन्होंने मांग की है कि सभी सरकारें हस्तक्षेप करके बड़ी परियोजनाएं स्थापित करें जिनके माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सर्जन को सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। अन्यथा समाज घोर संकट में फंस जाएगा। ये विचार आइ एल ओ के एक विशेषज्ञ श्री समीद ने व्यक्त किये थे और इस तथ्य को आइ एल ओ की ओर से हाल ही में जारी की गयी एक रिपोर्ट में भी उल्लिखित किया गया है।

इन्हीं परिस्थितियों में जी-7 देशों, बहुराष्ट्रीयकृत विश्व अर्थव्यवस्था के उन्नायकों की एक बैठक 1-2 अप्रैल 1996 को लिले (फ्रांस) में हुई। अर्थात् यह बैठक एक सूत्रीय कार्यसूची पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी। यह कार्यसूची थी- बेरोजगारी की समस्या। बाढ़-द्वार जिन्हें स्वयं उनकी वैश्वीकृत तथा उदारीकृत अर्थव्यवस्था ने खोला है। उनकी समस्या थी कि उनके अपने देशों में विद्यमान 2.20 करोड़ बेरोजगार लोगों को काम पर वापस कैसे लिया जाए। वे इस समस्या से ग्रसित हैं, इसमें संदेह नहीं। किन्तु वे जिस ढंग से इस समस्या का समाधान चाहते हैं वह निर्बाध रूप से चलने वाली मुक्त बाजार की व्यवस्थाओं तथा एक 'अन्तर्राष्ट्रीयतावादी' नीति के मध्य 'तीसरे मार्ग' ढूंढ़ना ही है और अन्ततोगत्वा यह समाधान सुधार की उन्हीं नीतियों को बढ़ाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है अर्थात् बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा निगमों का बर्चस्व विश्व पर होना ही चाहिए।

उपरोक्त समाधान के चलते विश्व भर का श्रमिक वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए जबरदस्त संघर्ष कर रहा है, सबसे बढ़ कर वह अपने रोजगारों और आर्थिक स्थितियों में क्षरण को रोकने के लिये प्रतिरोधात्मक कार्रवाईयां करने में लगा हुआ है। इस अवधि में आपने देखा होगा कि फ्रांस में सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों, जर्मनी के श्रमिकों और निःसंदेह रूस तथा पूर्वी युरोप के देशों जिन्होंने विकास के पूंजीवादी पथ तथा बाजार अर्थव्यवस्था को अपना लिया था, के श्रमिकों ने हड़ताल की व्यापक कार्रवाईयों की हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी पूर्व रंगभेदी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष के एक सहयोद्धा संगठन कोसाटू की ओर से भी तथाकथित बाजार अर्थव्यवस्था के सुधारों के विरोध में संघर्ष चलाये गए हैं। श्री लंका में ऊर्जा क्षेत्र के श्रमिकों ने हाल ही में लंका इलैक्ट्रिक कम्पनी तथा सीलोन इलेक्ट्रिक सिटी बोर्ड का निजीकरण करने के विरोध में जबरदस्त हड़ताल की थी जिसके चलते पूरा देश कई दिनों तक अंधकार में डूब गया था और उसे पानी के बिना रहना पड़ा।

राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करने से पूर्व मैं रूस तथा अन्य भूतपूर्व कम्युनिस्ट देशों में घटने वाली घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं।

रूस इन दिनों समाचार पत्रों के कालमों की शोभा बढ़ा रहा है। पूंजीवादी एक महान खतरे की जोर-जोर से दुहाई देने लगे हैं, यह महान खतरा 16 जून के राष्ट्रपति चुनाव में कम्युनिस्टों की सत्ता में संभावित वापसी के कारण दिखायी देने लगा है। नाटो देश येलत्सिन को भारी-भरकम धन राशियां देकर खड़ा रहने के लिए सहायता दे रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रूस के लिए 10.2 करोड़ डालर के आपातकालीन ऋण को स्वीकृति दे दी है, जर्मनी ने अतिरिक्त 2.7 करोड़ डालर का ऋण दिया है, फ्रांस तथा जापान ने भी घोषणा की है कि वे येलत्सिन की सहायता करेंगे ताकि वह सफलतापूर्वक राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकें और कम्युनिस्ट प्रत्याशी को पराजित कर सकें। इस सम्बंध में एक विस्तृत लेख 'पोलिटीकल एण्ड इकनामिक वीकली' के 18 मई के अंक में प्रकाशित हुआ है। उस लेख के एक पैरे का उल्लेख मैं यहां कर रहा हूं। उससे

पता चलता है कि किस प्रकार बड़े पूंजीवादी देश राष्ट्रपति पद के लिए आगामी चुनावों में येलत्सिन की सम्भावित पराजय को लेकर चिंतित हैं।

*"वायस आफ अमेरिका तथा रेडियो फ्री युरोप के भारी सैन्य बल के प्रचार अस्त्र अत्यंत आलंकारिक उन्माद के साथ शीत युद्ध की एक नयी पिच पर अपनी कला के जौहर दिखा रहें हैं। उनका संदेश स्पष्ट है; बुराइयों का साम्राज्य ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच चुका है; 'कौमीज' (कम्युनिस्ट) 'लोकतंत्र' की जादूगरी का खेल दिखाने के लिए आ रहे हैं; पिछले पांच वर्षों के 'सुधारों' का अनुभव अत्यंत कड़ुआ एवं दु:खदायी है; लेनिनवाद अपनी समस्त भयावहताओं के साथ पुनर्स्थापित हो रहा है; पूर्वी युरोप अस्थिर हो जाएगा। किसी भी मूल्य पर इस 'लाल' आक्रमण को रोका जाए। सामान्य की भांति इस बार भी ऐसे वक्तव्यों को 'मानव अधिकारों', 'बहुलतावाद', 'आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिरता' तथा 'आर्थिक सुधारों' के निर्वाण जैसे शब्दों का पुट दिया गया है।"

यहां हम देखते हैं कि किस निल्लर्जता के साथ साम्राज्यवाद जनता की इच्छा का दमन करने के लिये रूस के चुनावों में हस्तक्षेप कर रहा है। साम्राज्यवाद तो साम्राज्यवाद ही है। हिंसक बाघ कभी अपनी प्रवृति का त्याग नहीं कर सकता।

हम जानते हैं कि वर्ष 1991 में साम्राज्यवादियों ने बढ़ चढ़ कर दावे किये थे कि साम्यवाद मर चुका है और वह कभी वापस नहीं आएगा। अब वही लोग हो हल्ला मचा रहें हैं कि रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गेनादी जुगानोव रूस में सत्ता पर आसीन हो रहे हैं और साम्यवाद लगभग वापस लौट रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कम्युनिस्टों ने रूस में दिसंबर के संसदीय चुनावों में बहुमत प्राप्त किया था। यदि चुनाव न्यायपूर्ण ढंग से होते हैं तो पार्टी का नेता इस बार देश का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अत: वे लोग साम्यवाद की मृत्यु के सम्बन्ध में जो दावे करते रहे हैं उन पर एक बार पुन: प्रश्न चिह्न लग गया है। इसके साथ ही हमें इस तथ्य को भी नोट करना होगा कि कम्युनिस्ट लगभग सभी पूर्व कम्युनिस्ट देशों में सत्ता में आ गए हैं।

पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुलगारिया तथा स्लोवाकिया में वे पूंजीवादियों द्वारा साम्यवाद की मृत्यु सम्बन्धी घोषणा किये जाने के शीघ्र पश्चात् ही चुनावों के माध्यम से सत्तारूढ़ हो गए थे। पूर्व पूर्वी ब्लाक का एक प्रमुख भाग एक बार पुन: कम्युनिस्ट शासन के अन्तर्गत आ गया है और उन्होंने भिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यक्रम लागू किये हैं। इसके अतिरिक्त इटली में सम्पन्न हाल ही के चुनावों में भी कम्युनिस्ट उभर कर सामने आए हैं और उन्होंने अन्य दलों के साथ मिल कर गठबंधन सरकार का गठन किया है। साइप्रस में भी कम्युनिस्टों ने बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। इन घटनाओं ने उन दावों को निर्मूल करार दिया है जिनके अन्तर्गत कहा जाता था कि आर्थिक उदारीकरण तथा सुधारों, भूमण्डलीयकृत समन्वित अर्थ व्यवस्था, गैट तथा ऐसे ही विभिन्न प्रकार के हथकण्डों जिनके माध्यम से पूंजीवादी सत्ता में आए हैं, के इस दौर में साम्यवाद कभी वापस लौट नहीं सकता।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम अधोलिखित व्यापक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं:

क) वर्ष 1991 में सोवियत संघ तथा पूर्वी युरोपीय समाजवादी देशों के पराभव के पश्चात् बड़ी शक्तियों (पूंजीवादी) ने वादा किया था कि वे वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास से लाभ उठाते हुए संकट मुक्त पूंजीवाद का निर्माण करेंगे; उनके इस वादे ने मूर्त रूप नहीं लिया है और वर्तमान में ये पूंजीवादी देश भारी संकट की दलदल में फंसे हुए हैं।

ख) बेरोजगारी की सदाबहार वृद्धि की समस्या के चलते उन्हें भी औद्योगिक एवं विकास गतिविधियां शुरू करने के लिए विवश होना पड़ा है। दूसरे शब्दों में यह सभी प्रकार के प्रतिबंधों मुक्त पूंजीवाद की अपेक्षा 'तीसरा' मार्ग है जो रोजगार का सर्जन करेगा। पूंजीवाद के अन्तर्गत ये बातें निरर्थक हैं।

ग) विकसित एवं अर्ध विकसित समाजों में बढ़ रही बेरोजगारी के चलते श्रम के क्रेता बाजार उत्पन्न हो गए हैं। नियोक्ता- अर्थात् पूंजीपति नए रंगरूटों (श्रमिकों) के लिए कम वेतनों एवं अल्प सुविधाओं वाले रोजगार की शर्तें निर्धारित करते हैं। वे पहले से रोजगार पर लगे अपने श्रमिकों की सुविधाओं जिनमें वेतन भी सम्मिलित है, को कम करने के लिये कदम उठा रहे हैं।

घ) इसलिए, श्रमिक वर्ग एक अत्यंत गम्भीर स्थिति का सामना कर रहा है, उन्हें पूंजीपति वर्ग के सीधे-सीधे दो-दो हाथ करने पड़ रहे हैं और वह नये समाज अर्थात् समाजवाद के निर्माण हेतु संघर्ष चला रहा है। श्रमिक वर्ग सांगठनिक एवं विचारधारक दृष्टि से स्वयं को इस संघर्ष के लिये तैयार कर रहा है।

चुनावों में जबरदस्त राजनीतिक युद्ध के पश्चात् हमें आंशिक सफलता मिली है। कांग्रेस (इ) सत्ता से हाथ धो बैठी है, इसमें संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक दिया गया है। यद्यपि नव गठित संयुक्त मोर्चा सरकार बनाने में सफल रहा है तथापि उसका मार्ग अनेकानेक कांटों (कठिनाइयों) से अटा पड़ा है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है सुधारों ने भूमण्डलीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। उन्होंने हमारे देश में भी गहरी घुसपैठ कर ली है और साम्राज्यवादियों तथा भारत के इजारेदार घरानों के बढ़ते दबावों के अन्तर्गत हमारी अर्थव्यवस्था के भीतर गहराई तक अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया है और उनके बने रहने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अत: इस स्थिति में हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हम अपने संघर्षों के बल पर ही इस आंशिक विजय को प्राप्त करने की वर्तमान स्थिति तक पहुंच सके हैं और अभी भी हमारे सामने अनेक खतरे मुंह बांए खड़े हैं। अभी भी हमने श्रमिकों के विशाल वर्गों तथा पीड़ित जनता की अन्य श्रेणियों को लामबंद करना है, अपनी एकता को और सुदृढ़ बनाना है तथा अपने संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए उन्हें नये आयाम देने हैं। जन संघर्षों के दबाव से ही हम परिवर्तन

की प्रक्रिया को तीव्रतर कर सकते हैं तथा देश की आर्थिक सम्प्रभुता की रक्षा कर सकते हैं और राष्ट्रीय प्रगति को सुनिश्चित बना सकते हैं।

हमें एक क्षण के लिये भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता में आने के लिये उत्पन्न किये गए खतरे को भुलाना नहीं होगा; यद्यपि उन्हें सत्ता से निकाल बाहर कर दिया गया है और संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा है। साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध जनता को लामबंद करने सम्बन्धी हमारा कार्य भाजपा सरकार के पतन के साथ समाप्त नहीं हुआ है। वास्तव में हमें और भी जोर-शोर से एवं पूर्ण शक्ति के साथ यह काम करना होगा, इसके लिये हमें उपलब्ध समय तथा अवसरों जिन्हें हमने भाजपा सरकार के पतन तथा केन्द्र में संयुक्त मोर्चा सरकार के सत्तारूढ़ होने के फलस्वरूप प्राप्त किया है, का सघन सदुपयोग करना होगा।

साथियो, मैं देश में चुनाव परिणामों के विस्तार में जाना नहीं चाहता। तथापि मैं आपको उस शानदार विजय के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं जो हमने पश्चिम बंगाल राज्य में प्राप्त की है। कामरेड ज्योति बसु तथा उनके साथ साथी मंत्रियों की टीम इन चुनावों में पांचवीं बार सत्ता में आई है। भारतीय राजनीति के इतिहास में यह अनूठी घटना है। कांग्रेस (इ) ने पश्चिम बंगाल में हमें पराजित करने के लिये कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ी थी किन्तु इसमें वह बुरी तरह असफल रही है। आपके तथा वाम पक्ष की ओर से मैं कामरेड ज्योति बसु को यह विजय श्री प्राप्त करने के लिये बधाई देता हूं। केरल में भी वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने चुनावों में विजय प्राप्त की है तथा कामरेड ई के नायनार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। मतदाताओं द्वारा कांग्रेस (इ) के नेतृत्व वाले मोर्चे की चुनावों में भारी धुनाई की गई है और विधान सभा में भारी बहुमत प्रदान किया है। मैं इस शानदार सफलता के लिये वाम एवं लोकतांत्रिक मोर्चे को भी बधाई देता हूं।

मैं और अनेक घटनाओं के विवरण में जाना नहीं चाहता। महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में इन पर सविस्तार प्रकाश डाला है। मैं स्वयं को केवल कुछेक बातों या घटनाओं तक ही केंद्रित रखूंगा। भिलाई वर्किंग कमेटी बैठक ने सभी राज्यों में तत्काल आवश्यक कदम उठा कर सदस्य संख्या बढ़ाने और इसके माध्यम से संगठन को सुदृढ़ बनाने का विशेष निर्णय लिया था। हम इसमें किस सीमा तक सफल हुए हैं, मैं नहीं जानता। पिछले पांच वर्षों में हमारे द्वारा बड़े-बड़े संघर्ष किये जाने के फलस्वरूप सी आइ टी यू की प्रतिष्ठा श्रमिकों तथा कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी में बढ़ी है। तथापि यह तथ्य हमारी सांगठनिक शक्ति में परिबिम्बित नहीं होता। हमें अल्पावधि में ही अपनी इस दुर्बलता को दूर करना होगा। भूमण्डलीयकृत आर्थिकता की व्यवस्था में भले ही राजनीतिक परिदृश्य बदल गया हो तथापि श्रमिकों के अधिकरों एवं सुविधाओं को छीन लिये जाने की प्रत्येक सम्भावना विद्यमान है। हम अपनी सांगठनिक शक्ति को सुदृढ़ बना कर ही इसके विरुद्ध सफल संघर्ष कर सकते हैं। जहां हमें सामरिक क्षेत्रों में अपनी यूनियनों के कार्यों पर पर्याप्त बल देना होगा वहीं हमें अनेक प्रकार के हमलों का सामना कर रहे असंगठित क्षेत्र में कार्यरत भारत के बहुसंख्यक श्रमिकों को अपने संगठन की पंक्तियों में खींच लाने तथा उनकी ओर अपना ध्यान केन्द्रित करने के अपने उत्तरदायित्व को विस्मृत नहीं करना होगा। उन्हें न रोजगार की सुरक्षा प्राप्त है और न ही न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाती है। इसलिए सी आइ टी यू की ओर से इस क्षेत्र में अपनी पूर्ण शक्ति एवं ऊर्जा को केन्द्रित करने पर बल देना स्वाभाविक ही है। समन्वय समिति जिसे हमने इस क्षेत्र में संगठित किया था, ने कुछ श्लाघनीय कार्य करना आरम्भ कर दिया है। हमारी यूनियनों के संगठन की दृष्टि से सुदृढ़ क्षेत्रों को वित्तीय संसाधन जुटाने के साथ-साथ इस सम्बन्ध में विशेष पहलकदमी करनी होगी। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत यूनियनों की समन्वय समिति द्वारा इस दिशा में लिये गए निर्णय को सभी राज्य समितियां गम्भीरता से लें और उन्हें कार्यरूप दिया जाना सुनिश्चित बनाएं। उद्योगों में से एक कपड़ा उद्योग इन दिनों गम्भीर संकट में है। यद्यपि इस उद्योग में ट्रेड यूनियनों की शक्ति बढ़ रही है तथापि अखिल भारतीय स्तर पर यह पर्याप्त नहीं हैं। हमने स्थिति की समीक्षा करते हुए इस उद्योग में भी समन्वय समिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य यही था कि समय रहते एक समुचित फेडरेशन का गठन किया जाए। इस समन्वय समिति की सावधि बैठकें होती हैं, उसके द्वारा निर्णय लिये जाते हैं और उन निर्णयों को कार्यरूप दिया जाता है। तथापि इस उद्योग की विशालता तथा संगठन में व्याप्त दुर्बलता को देखते हुए इस उद्योग की ओर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इसलिए राज्य समितियों को कोयम्बटूर कन्वेंशन में लिये गए सांगठनिक निर्णयों के अनुसार समन्वय समिति को सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि कपड़ा उद्योग के प्रत्येक केन्द्र में हमारा संगठन सुदृढ़ हो तथा कपड़ा श्रमिकों की एक नियमित फेडरेशन का गठन किया जा सके।

हमारे द्वारा संचालित औद्योगिक फेडरेशनें (महासंघ) यद्यपि अच्छा काम कर रही हैं तथापि उनकी ओर से अभी तक सी आइ टी यू केन्द्र को उपर्युक्त रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है। इसके कारण हम उनके सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यक्ष उल्लेख करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि दो-तीन संगठनों को छोड़ कर शेष सभी संगठनों का काम पिछड़ा हुआ है। हमारी राज्य समितियों द्वारा बीड़ी श्रमिकों तथा मछुआरों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए और उन्हें संगठन की पंक्तियों में लाया जाना चाहिए क्योंकि श्रमिकों की ये श्रेणियां भी सरकारी नीति के चलते गम्भीर कठिनाईयां झेल रही हैं। हमारे सांगठनिक निर्णयों को गम्भीरतापूर्वक लिया जाए और उन्हें कार्यरूप दिया जाए; मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें।

ट्रेड यूनियन एकता

ट्रेड यूनियन एकता के प्रश्न पर विचार करने के लिये हमने एटक के नेताओं के साथ बैठक की है। हमारे मध्य कुछ प्रारम्भिक बातचीत हुई

है और हमने जून के मध्य में पुन: बैठक करने का निर्णय लिया था। इसी मध्य उन्होंने एच एम एस के साथ दोनों संगठनों के पारस्परिक विलय के सम्बन्ध में बातचीत की है और समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर सांगठनिक कदम उठाने का निर्णय लिया है। तथापि हमने देखा है कि उनके द्वारा जारी किये गए घोषणा पत्र सशर्त हैं। उनका कहना है कि ट्रेड यूनियनें गैर राजनीतिक संगठन होने चाहिए। ट्रेड यूनियन एकता के प्रश्न पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। परिसंघ का विचार जो हमने दिया था, अभी भी सही है और हम अनुभव करते हैं कि ट्रेड यूनियन एकता का सही नारा सर्वसामान्य मांगों के लिये संघर्ष करना है और समुचित अवधि में सांगठनिक सौहार्द तथा एकता स्थापित की जा सकेगी। किन्तु एटक ने यूनियनों के पारस्परिक विलय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वे इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे-धीरे विलय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ट्रेड यूनियन एकता के सम्बन्ध में अपने विस्तृत दृष्टिकोण से हमें अवगत नहीं कराया है जबकि हमारी संयुक्त बैठक मध्य जून में करने का प्रस्ताव है। हमें अपने दृष्टिकोण के सम्बन्ध में निर्णय लेना होगा।

इसलिए मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में अपने-अपने विचार व्यक्त करें।

एक और महत्वपूर्ण बात जिसका मैं यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं वह बी टी आर स्मारक भवन के सम्बन्ध में है। हमने उसके लिये भूमि प्राप्त कर ली है। हमें उसका कब्जा लेना है और भवन निर्माण का काम शुरू करना है। हमने भवन का नक्शा अविलम्ब तैयार करने के लिये अपने वास्तुकार (आर्किटेक्ट) के साथ सम्पर्क किया है।

साथियों, इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि हम इसके लिए आवश्यक धन तुरंत इकट्ठा करें। हम जानते हैं कि भवन निर्माण में करोड़ों रुपये लगेंगे। हमारी अपनी इच्छाओं के अनुरूप दिल्ली में एक उपयुक्त कार्यालय हो, वह केवल सी आइ टी यू का केन्द्रीय कार्यालय ही नहीं होना चाहिए; हम चाहते हैं कि वह देश के सभी श्रमिक संघों का केन्द्रीय कार्यालय बने। कामरेड बी टी आर की याद में हमें इस केन्द्रीय कार्यालय जिसमें ट्रेड यूनियनों के कार्यों का प्रभावी ढंग से निष्पादन करने के लिये सभी आधुनिक सुविधाएं हों, के भवन का निर्माण कार्य कराना होगा! साथियो, मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को गम्भीरता से लेंगे और इस सम्बन्ध में लिये निर्णयों को कार्यरूप देने के लिये तत्काल कार्रवाई करेंगे।

श्रमिक वर्ग की एकता अमर रहे

दिनांक 2-6-1996

उड़ीसा में कपड़ा श्रमिकों का राज्य स्तरीय सम्मेलन

सी आइ टी यू की उड़ीसा राज्य समिति द्वारा 17 मार्च 1996 को यात्री निवास भुवनेश्वर में कपड़ा श्रमिकों के एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मिल, हथकर्घा तथा विद्युतकर्घा अर्थात् तीनों क्षेत्रों के श्रमिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर सी आइ टी यू का ध्वज लहराया गया तथा शहीद बेदी पर फूल चढ़ाए गए। ओ टी एम श्रमिक केन्द्र के उपाध्यक्ष कामरेड दीनबंधु गादन, सोनपुर स्पिनिंग मिल श्रमिक यूनियन के उपाध्यक्ष कामरेड राजेन्द्र साहू, बारीपदा स्पिनिंग मिल वर्करस यूनियन के उपाध्यक्ष कामरेड शंभूनाथ जेना, बी टी एम के कामरेड हरिशंकर शर्मा और बरौनी पावरलूम एम्पलाइज यूनियन के अध्यक्ष कामरेड जी सी पटनायक पर आधारित अध्यक्ष मण्डल ने सम्मेलन की कार्रवाई का संचालन किया। दिवंगत नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की स्मृति में शोक प्रस्ताव पस्तुत किया गया और एक मिनट का मौन रख कर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की गई।

सी आइ टी यू की उड़ीसा राज्य इकाई के अध्यक्ष कामरेड शिवाजी पटनायक संसद सदस्य (अब भूतपूर्व) ने औपचारिक रूप से सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिनिधियों को भी सम्बोधित किया। सी आइ टी यू की राज्य इकाई के महासचिव कामरेड लम्बोदर नायक ने प्रतिनिधियों का अभिवादन किया। राज्य समिति की ओर से कामरेड प्रदीप दास ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। कामरेड नरहरी परुस्ती, धानेश्वर साहू, राजेन्द्र साहू, हरिशंकर शर्मा, श्रीनिवास सुबधिरारी, विक्रम जेना, बिंदु बिहारी परुस्ती, शंभुनाथ जेना इत्यादि साथियों ने रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया। सम्मेलन में सर्वसम्मति से रिपोर्ट को पारित किया गया। कामरेड सत्यनंद बहेड़ा द्वारा एक विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जबकि कामरेड पीताम्बर लेंका ने उसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव में सराला को आपरेटिव स्पिनिंग मिल्स की तालाबंदी समाप्त करने की मांग की गई। ज्ञातव्य है कि 17-6-96 से मिल में प्रबंधन द्वारा गैर कानूनी तालाबंदी की गई है जिसके चलते 1500 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं।

सम्मेलन में एक 15 सदस्यीय राज्य स्तरीय समन्वय समिति का चुनाव किया गया। उड़ीसा में कपड़ा श्रमिकों के आंदोलन तथा संगठन में सामंजस्य स्थापित करने के लिये कामरेड प्रदीप दास की समिति का संयोजक बनाया गया।

सम्मेलन ने केन्द्रीय सरकार कपड़ा नीति और उसके साथ-साथ आर्थिक नीति की कड़ी आलोचना की। उड़ीसा की कांग्रेस (इ) सरकार के श्रमिक विरोधी आचरण की भी कड़ी निंदा की गई। सम्मेलन में कपड़ा श्रमिकों को वेतनों, महंगाई भत्ते, बोनस का भुगतान न करने; ई एस आइ तथा ई पी एफ जमा न कराए जाने और स्पिनिंग मिलों तथा कम्पोजिट मिलों की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने, हथकर्घा तथा विद्युत कर्घा मिलों में कार्यरत श्रमिकों की दुर्दशा पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

न्यूनतम कार्यक्रम के नकारात्मक मुद्दों पर आलोचना करने के अधिकार के साथ संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन करेंगे

□ पी के गांगुली

[सी आइ टी यू वर्किंग कमेटी की बैठक 7-9 जून, 1996 को नयी दिल्ली में सम्पन्न हुई। वर्किंग कमेटी ने श्री एच डी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा घोषित सांझे न्यूनतम कार्यक्रम का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए उसका समर्थन करने का निर्णय लिया। किन्तु इसके साथ ही सी आइ टी यू ने इस कार्यक्रम के कुछ विशेष नकारात्मक मुद्दों पर आलोचना करने के अपने अधिकार को अक्षुण बनाए रखा है। कार्यक्रम की गहन विवेचना करने के पश्चात् सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया।

सी आइ टी यू के अध्यक्ष कामरेड ई बालानंदन जो उन दिनों अस्वस्थ चल रहे थे, की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कामरेड समर मुखर्जी ने बैठक की अध्यक्षता की। सचिव कामरेड पी के गांगुली ने अध्यक्षीय भाषण पढ़ा और उनके पश्चात् महासचिव कामरेड एम के पंधे ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके साथ ही बैठक में रिपोर्ट पर बहस शुरू हो गई।

विश्व पूंजीवाद के संकट तथा विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के अन्तर्गत जारी वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करते हुए अध्यक्ष ने विश्वव्यापी स्तर पर उसके श्रम वर्ग पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष ने कहा कि भारत की स्थितियों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिये। यद्यपि घोर चुनावी युद्ध के पश्चात् केन्द्र में संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में आई है तथापि सुधारों ने भूमण्डलीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने भारत ने में दूर-दूर तक प्रभाव डाला है। साम्राज्यवादियों के बढ़ रहे दबावों के अन्तर्गत इनके बने रहने तथा और गहराई तक घुसपैठ किये जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। अत: अभी हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन करते हुए हमें भाजपा के विरुद्ध देश की एकता तथा अखण्डता एवं उसके धर्म निर्पेक्ष स्वरूप की रक्षा करनी होगी। अपने संघर्षों को जारी रखना होगा, कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई आइ एम एफ निदेशित आर्थिक नीतियों तथा उनके विनाशकारी परिणामों के विरुद्ध श्रमिकों के विशालतर वर्गों को लामबंद करना होगा (अध्यक्षीय भाषण का मूल पाठ इसी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है: सम्पादक)।

महासचिव की रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्थिति पर सविस्तार प्रकाश डाला गया था तथा नरसिम्हा राव सरकार की आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में श्रमिकों के अनुभवों का वर्णन किया गया था। उसमें दिन-प्रतिदिन खराब हो रही आर्थिक स्थिति, देश में फैलते जा रहे ऋणों के मकड़जाल, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण, बढ़ती चली जा रही औद्योगिक बीमारी, बी आइ एफ आर की कार्यप्रणाली और तथाकथित संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम के दुष्परिणाम स्वरूप हजारों-हजार लोगों की रोजगारहीनता इत्यादि प्रश्नों पर विचार किया गया था। उसमें वर्किंग कमेटी की भिलाई बैठक के बाद की अवधि में श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा किये गए उल्लेखनीय संघर्षों पर भी प्रकाश डाला गया था। इन संघर्षों में 29 नवंबर को बंगाल में हुई जूट हड़ताल, दिल्ली तथा अन्य राज्यों में 23 नवंबर को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल, बीड़ी श्रमिकों के संघर्ष, 18 जनवरी की मत्स्य श्रमिकों (मछुआरों) की देशव्यापी हड़ताल, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों का संघर्ष, वित्तीय क्षेत्र के श्रमिकों की हड़ताल तथा संघर्ष, कपड़ा श्रमिकों का संघर्ष, प्रतिगामी पेंशन योजना के विरुद्ध 23 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल, सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों तथा कामकाजी महिलाओं इत्यादि के संघर्ष। रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकों पर ही सी आइ टी यू: आइ एल ओ कार्यक्रम पर प्रकाश डाला गया। उसमें सी आइ टी यू के बढ़ रहे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की जानकारी भी दी गई। उसमें संगठनात्मक रिपोर्ट पर कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सविस्तार एवं आलोचनात्मक विवेचना की गई।

नयी स्थिति तथा श्रमिकों के कार्य विषय पर चर्चा करते समय रिपोर्ट में संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन किया गया और वाम, लोकतांत्रिक एवं धर्मनिर्पेक्ष शक्तियों की भाजपा के नेतृत्व वाली साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध एकता का अनुमोदन किया गया। तथापि रिपोर्ट में प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा पूर्वगामी नरसिम्हा राव सरकार की उदारीकरण सम्बन्धी नीतियों के समर्थन में दिये गए कुछ वक्तव्यों पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई। ये वही नीतियां हैं जिनके विरुद्ध श्रमिक वर्ग ने पिछले पांच वर्षों में घोर संघर्ष किया है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया कि गैर कांग्रेस, गैर भाजपा देव गौड़ा सरकार पर श्रमिक वर्ग में कुछ आशाओं का जन्म लेना स्वाभाविक ही है और श्रमिक वर्ग समझता है कि कांग्रेस सरकार की नीतियों को उल्लेखनीय सीमा तक तिलांजलि दी जाएगी, उन्हें आशा थी कि बहुराष्ट्रीयों के निर्बाध अनुप्रवेश को रोका जाएगा और

सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद किया जाएगा, उन्हें आशा थी कि बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित किया जाएगा; बेरोजगारी के बढ़ते स्तर को नीचे लाया जाएगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के माध्यम से बढ़ते मूल्यों पर अंकुश लगाया जाएगा और उन्हें कम किया जाएगा। उन्हें आशा थी कि औद्योगिक सम्बन्धों पर एक नया विधेयक लाया जाएगा जिसमें ट्रेड यूनियन अधिकारों को सुनिश्चित बनाया जाएगा, गुप्त मतदान के माध्यम से श्रमिक संघों को मान्यता दी जाएगी और प्रबंधन में श्रमिकों की समुचित भागीदारी होगी। उन्हें यह भी आशा थी कि सरकार एक न्यायोचित पेंशन योजना लागू करेगी और सामाजिक सुरक्षा के कदम उठाए जाएंगे। उससे भी आगे जाते हुए उन्हें आशा थी कि न्यूनतम वेतन की गारंटी देते हुए विशाल असंगठित क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा और खेत मजदूरों के लिये व्यापक कानून बनाया जाएगा तथा गरीब कृषकों की दशा सुधारने के लिये भूमि सुधार किये जाएंगे।

रिपोर्ट में बताया गया कि श्रमिक वर्ग तथा अन्य परिश्रमी लोगों का समर्थन देव गौड़ा सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होगी, यह समर्थन उसकी पूर्वगामी कांग्रेस सरकार को प्राप्त नहीं था; यही समर्थन कांग्रेस तथा भाजपा के विरुद्ध सरकार की शक्ति तथा स्थायित्व की गारंटी होगी। रिपोर्ट में सी आइ टी यू यूनियनों को आह्वान किया गया कि वे इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करें और देश की आर्थिक सम्प्रभुता तथा इसके धर्मनिर्पेक्ष स्वरूप की रक्षा के लिये भाजपा तथा कांग्रेस के हथकण्डों के विरुद्ध संघर्ष को सुदृढ़ता प्रदान करें।

रिपोर्ट पर बहस में 24 सदस्यों ने भाग लिया जबकि सोलह सदस्य संगठन पर बहस में सम्मिलित हुए। क्योंकि उस समय तक संयुक्त मोर्चा का सांझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषित हो चुका था, इसलिये स्वाभाविक रूप से बहस कार्यक्रम और उसके साथ-साथ महासचिव की रिपोर्ट पर केन्द्रित रही। कार्यक्रम के सकारात्मक पक्षों का समर्थन करते हुए सदस्यों ने उसके नकारात्मक पक्षों पर तीखी आलोचना भी की, वे विशेष रूप से बीमा क्षेत्र तथा टेलीकाम क्षेत्र की बहुराष्ट्रीयों के लिये खोलने और पूंजीविनिवेश पर अधिक मुखर थे।

संगठन पर सदस्यों ने सचेतन रूप से आत्म आलोचनात्मक रुख अपनाया। उन्होंने निर्धारित कार्यों के कार्यान्वयन में रही दुर्बलताओं का उल्लेख किया और इन दुर्बलताओं को दूर करने सबन्धी सम्बन्धित राज्य समितियों की योजनाओं की जानकारी दी।

कामरेड पंधे द्वारा बहस का उत्तर दिये जाने के पश्चात् रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। उसके पश्चात् कामरेड ए के पद्मनाभन ने वर्तमान स्थिति तथा श्रमिक आंदोलन विषय पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका कामरेड नीरेन घोष द्वारा अनुमोदन किया गया। अनेक सदस्यों ने प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये और उसमें अनेक संशोधन सुझाए। प्रस्ताव में संयुक्त मोर्चा सरकार के गठन का स्वागत किया गया तथा केन्द्र में सत्ता हस्तगत करने सम्बन्धी भाजपा के खेल को विफल बनाने में वाम तथा धर्मनिर्पेक्ष दलों की सफलता पर गहरा संतोष व्यक्त किया गया। प्रस्ताव में जहां संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा अपनाए गए न्यूनतम कार्यक्रम के सकारात्मक पक्षों पर प्रकाश डाला गया वहीं उसके नकारात्मक पक्षों जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, की पुष्टि नहीं की गई। सरकार से मांग की गई कि वह सभी विवादास्पद मुद्दों पर श्रमिक संघों के साथ विचार विमर्श करे और कार्यक्रम के सकारात्मक पक्षों को समुचित ढंग से कार्यरूप दें।

वर्किंग कमेटी ने संयुक्त मोर्चा सरकार के समर्थन में अन्य श्रमिक संघों के साथ बातचीत करने तथा आंदोलनात्मक कार्यक्रम का निर्णय लेने के लिये राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया।

कामरेड समर मुखर्जी ने बहस का समापन किया। बैठक समाप्ति के पश्चात् कामरेड किम इल सुंग की प्रथम मृत्यु वार्षिकी के उपलक्ष्य में शोक सभा का आयोजन किया गया। भारत में कोरिया जनवादी लोक गणराज्य के राजदूत ने भी इस सभा में भाग लिया।

वर्किंग कमेटी का प्रमुख प्रस्ताव
वर्तमान स्थिति तथा श्रमिक आंदोलन

सी आइ टी यू वर्किंग कमेटी की 7-9 जून 1996 को नयी दिल्ली में सम्पन्न यह बैठक केन्द्र में संयुक्त मोर्चा सरकार की स्थापना का स्वागत करती है। वर्किंग कमेटी ने गलत हथकण्डे अपना कर भी केंद्र में सत्ता हस्तगत करने के लिये भाजपा की योजना को विफल बनाने में वाम एवं धर्मनिर्पेक्ष शक्तियों की सफलता पर गहरा संतोष व्यक्त किया। वाजपेयी सरकार के 13 दिवसीय कार्यकाल का अनुभव, राष्ट्रपति का भाषण तथा आविश्वास प्रस्ताव पर लोक सभा की कार्रवाईयां स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के दोमुखी चेहरे को उजागर कर देती हैं। इस दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में साम्प्रदायिक मंच के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त करते हुए न्यायप्रिय होने का मुखौटा ओढ़ा हुआ था।

वर्किंग कमेटी नोट करती है कि आम चुनाव श्रमिक वर्ग द्वारा दीर्घावधि तक विशाल स्तर पर किये गए संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुए हैं। श्रमिक वर्ग ने जनता की अन्य श्रेणियों के साथ मिल कर कांग्रेस (इ) के पंच वर्षीय शासनकाल में कोष/बैंक निदेशित आर्थिक नीतियों के साथ-साथ साम्प्रदायिक शक्तियों के विरोध में जबरदस्त संघर्ष किया है। तथाकथित नयी आर्थिक नीतियों ने जनता का जीवन अंधकारपूर्ण बना दिया है और श्रमिक वर्ग एवं जन साधारण के जीवन स्तर में भारी क्षरण हुआ है तथा स्वदेशी औद्योगिक आर्थिकता को गहरी क्षति पहुंचाई है और इसके चलते देश की आर्थिक सम्प्रभुता ही खतरे में पड़ गई है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। आंतरिक तथा बाह्य ऋणों में अपूर्व वृद्धि हुई है। कांग्रेस (इ) शासन के पांच वर्षों ने देश में अ-औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंधाधुंध निजीकरण किया गया है, बीमार इकाईयों को समाप्त कर दिया गया है और सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वदेशी उद्योगों के मूल्य पर विदेशी पूंजी को बेरोकटोक बढ़ावा दिया गया है, स्वदेशी क्षेत्र की

इकाईयों को बीमार किया गया है, उनकी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया, रोजगार विहीनता तथा बेरोजगारी को बढ़ावा दिया गया है। उसने नये रोजगारों का सर्जन करने की अपेक्षा पिछले रोजगारों की हत्या की है, और सभ्रांत लोगों एवं परिश्रमी जनता के मध्य आय की असमानता को और व्यापक बना दिया है।

केन्द्र में नयी संयुक्त मोर्चा सरकार ने श्रमिक वर्ग में बड़ी-बड़ी आशाओं को जन्म दिया है और लोगों को आशा थी कि नयी सरकार अपनी पूर्वगामी सरकार के कुकर्मों में सुधार लाएगी, निलज्जतापूर्ण ढंग से चल रहे निजीकरण को रोकेगी, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उद्यमों के सम्बन्ध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी और उन्हें पुनर्जीवित करने के काम में सक्रिय भूमिका निभाएगी, निजी क्षेत्र की बीमार इकाईयों के सम्बन्ध में भी वह ऐसा ही रुख अपनाएगी, स्वदेशी बाजार और यहां तक कि उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विदेशी पूंजी के अनुप्रवेश से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करेगी, रोजगार सर्जन की दिशा में सकारात्मक नया दृष्टिकोण अपना कर अपनी औद्योगिक एवं आर्थिक नीतियों में संशोधन करेगी और न्यायोचित भूमि सुधारों के माध्यम से ग्रामीण भारत के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी और खेत मजदूरों को समुचित वेतन दिये जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के माध्यम से मूल्य वृद्धि को रोका जाएगा।

इस स्थिति में स्पष्ट ही है। कि श्रमिक वर्ग ने संयुक्त मोर्चा सरकार से पात्रता तथा बोनस की सीमा समाप्त करने, आयकर के भुगतान पर छूट की सीमा को बढ़ाने; सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के भुगतान में पाई जाने वाली त्रुटियों को दूर करने; सार्वजनिक क्षेत्र की तथाकथित बीमार इकाईयों के कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन करने; निर्माण उद्योग के श्रमिकों, खेत मजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अन्य श्रमिकों को उनकी नौकरी की सुरक्षा, वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभों के मामले से सम्बन्धित कानूनों को लागू करने की अपेक्षाएं रखी थीं। स्थायी तथा स्थायी प्रकृति के अन्य कामों में ठेका व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिएं। त्रिपक्षीय मंच जिसे लगभग मरणासन्न अवस्था में ही पहुंचा दिया गया है, को सक्रिय तथा प्रभावी बनाया जाए। पिछली जनता दल सरकार द्वारा काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में सम्मिलित करने सम्बन्धी की गई पहलकदमी को नयी सरकार सिर चढ़ाएगी, इसके लिये श्रमिक वर्ग का आशाएं रखना स्वाभाविक ही है। श्रमिकों को यह आशा भी है कि नयी सरकार इस बार श्रमिक संघों के साथ विचार विमर्श करके प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की योजना को अंतिम रूप देगी तथा गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिये ठोस कदम उठाए जाएं और इन्हें अविलम्ब कार्यरूप दिया जाए। और निःसंदेह पेंशन के ज्वलंत मुद्दे की ओर उच्च प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाए और कम से कम सरकार पेंशन योजना को ऐच्छिक ही बना दे। यही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों तथा अन्य उद्यमों जो स्वयं अपनी-अपनी पेंशन योजना बनाने के लिये तत्पर हैं, को सरकार की ओर से ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिये। संयुक्त मोर्चा सरकार से यह आशा भी की जा सकती है कि वह भुगतान सम्बन्धी वेतन अधिनियम तथा श्रमिकों के लिये क्षतिपूर्ति अधिनियम संशोधन करने के लिये समुचित कदम उठाएगी, उसे श्रमिक समर्थक स्वरूप प्रदान करेगी तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाएगा, एस्मा तथा नासा जैसे पैशाचिक कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा।

वर्किंग कमेटी को इस तथ्य की अनुभूति है कि संयुक्त मोर्चा सरकार को अत्यंत जटिल स्थिति में काम करने की गम्भीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कांग्रेस (इ) के समर्थन पर निर्भर करती है जबकि भारतीय जनता पार्टी लोक सभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। यही नहीं, यह केन्द्र में गठबंधन सरकार के एक नये चरण का आरम्भ है।

तथापि, वर्किंग कमेटी का मानना है कि संयुक्त मोर्चा सरकार की एक न्यायोचित श्रमिक वर्ग समर्थक तथा गरीब समर्थक नीति होनी चाहिये और वह पूर्वगामी कांग्रेस (इ) सरकार की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति की विपरीत मोड़ दे। यदि ऐसा किया जाता है तो नयी सरकार को श्रमिकों तथा जन साधारण को स्थायी समर्थन प्राप्त होगा।

वर्किंग कमेटी संतोष के साथ नोट करती है कि संयुक्त मोर्चा सरकार के सांझे न्यूनतम कार्यक्रम में जैसे निर्गम नीति समाप्त करने, जन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, गुप्त मतदान के द्वारा यूनियन को मान्यता देने, उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के अनुप्रवेश को प्रतिबंधित करने, गृह आधारित तथा गांव आधारित उद्योग धंधों और लघु एवं मंझौले उद्योगों इत्यादि को संरक्षण देने जैसे विभिन्न जन हितैषी कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया है। वह बीमार उद्योगों के पुनर्वास, दरिद्रता उन्मूलन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने तथा पंचायतों के माध्यम से उन्हें कार्यरूप देने; संसद, विधान मण्डलों एवं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने; जन वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने तथा खेत मजदूरों के लिये व्यापक कानून बनाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये गए आश्वासनों का स्वागत करती है। वह राज्यों को और अधिक शक्तियां देकर देश की संघीय संरचना को सुदृढ़ बनाने और धर्मनिर्पेक्षता को बनाए रखने तथा सामाजिक न्याय का सरकार का प्रमुख नारा बनाने सम्बन्धी नयी सरकार की प्रतिबद्धताओं का स्वागत करती है। अयोध्या विवाद को संविधान की धारा 138 (2) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को सौंप देने सम्बन्धी सरकार द्वारा अपनाए गए सुस्पष्ट रुख पर यह बैठक राहत अनुभव करती है। यह बैठक देश की आत्मनिर्भरता प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने सम्बन्धी सरकार की प्रतिबद्धता तथा भ्रष्टाचार से मुक्त पारदर्शी शासन देने की घोषणा का हार्दिक स्वागत करती है। वर्किंग कमेटी विभिन्न मोर्चों पर संयुक्त मोर्चा सरकार को उसकी प्रतिबद्धताओं के लिये बधाई देती है तथा आशा करती है कि श्रमिक आंदोलन उसे पूर्ण समर्थन देगा। ये सभी कारक प्रेस के उस प्रचार को

झुठला देते हैं कि संयुक्त मोर्चा सरकार की नीतियां पूर्वगामी कांग्रेस (इ) सरकार की नीतियां की समदर्शी होंगी।

इसके साथ ही वर्किंग कमेटी सांझे कार्यक्रम के कुछ विशेष नकारात्मक पक्षों पर चिंतित है। वह बीमा क्षेत्र को इजारेदार तथा विदेशी पूंजी के लिये खोलने और टेलीकाम क्षेत्र का निजीकरण करने और पूंजी विनिवेश आयोग का गठन करके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी का विनिवेश करने सम्बन्धी सरकार के रुख का अनुमोदन नहीं कर सकती। वह सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों को पुनर्जीवित करने, बेलाडिला खदानों को बेचने के मामले पर मौन साधने, सेल के माध्यम से इस्को का आधुनिकीकरण करने जैसे मामलों पर जिनका उल्लेख सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में किया गया है, सरकार में स्पष्टता के अभाव पर चिंता व्यक्त करती है। यह बैठक सरकार की टैरिफ नीति का अनुमोदन भी नहीं कर सकती क्योंकि इससे स्वदेशी उद्योग पर भारी बोझ पड़ता है।

वर्किंग कमेटी आशा व्यक्त करती है कि जन समर्थन के चलते संयुक्त मोर्चा सरकार विभिन्न मोर्चों पर जन साधारण को तत्काल राहत पहुंचाएगी। इसके साथ ही वर्किंग कमेटी अनुभव करती है कि श्रमिक आंदोलन सरकार की सक्रिय भागीदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों को पुनर्जीवित करने; वित्तीय, दूरसंचार तथा अर्थव्यवस्था के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में भी बहुराष्ट्रीयों के अनुप्रवेश के विरुद्ध; निजीकरण तथा आयात उदारीकरण के विरुद्ध श्रमिकों को लामबंद करना जारी रखेगा। उसे अपनी पंक्तियों को भी साम्प्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में खींच लाना होगा। सी आइ टी यू भारत सरकार से मांग करती है कि वह श्रमिक संघों के साथ तत्काल बातचीत शुरू करे और श्रमिक संघों की सहमति से कदम उठाए, इससे सांझे न्यूनतम कार्यक्रम के सकारात्मक पक्षों को प्रभावी ढंग से कार्यरूप दिया जा सकेगा। सी आइ टी यू की वर्किंग कमेटी सभी सम्बद्ध यूनियनों तथा सभी सम्बद्धताओं से ऊपर उठकर सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग से अनुरोध करती है कि वह स्थिति की गम्भीरता; तथा साम्प्रदायिक शक्तियों के हथकण्डों को समझे और देश में व्याप्त इस जटिल स्थिति द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिये तैयार रहे। सी आइ टी यू को विश्वास है कि हम संयुक्त मोर्चा के सांझे न्यूनतम कार्यक्रम के सकारात्मक पक्षों को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने के लिये जन लामबंदी के माध्यम से देश तथा श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा कर सकते हैं। हमें भारत सरकार पर उन नीतियों का अनुसरण न करने के लिये दबाव डालना होगा जिनके चलते देश के श्रमिक वर्ग तथा परिश्रमी जनता के हितों पर विषय प्रभाव पड़ता हो।

□

सी आइ टी यू द्वारा एन टी सी की 40 मिलों को बंद करने के प्रयासों का विरोध

कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम (एन टी सी) की 40 मिलों के पुनर्जीवन हेतु एक नये पैकेज का प्रस्ताव किया है। समझा जाता है कि कपड़ा मंत्रालय तथा योजना आयोग द्वारा तैयार यह पैकेज नौवीं पंच वर्षीय योजना का भाग होगा जिसमें लगभग 40 मिलों में कामबंदी करने का विचार निहित है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ राज्यों द्वारा अतिरिक्त भूमि बेचने की कार्रवाई जिसकी वर्तमान योजना में कल्पना की गई थी, का विरोध किये जाने के कारण वर्तमान योजना समस्याओं के कोहरे में फंस गई है।

सी आइ टी यू स्पष्ट रूप से किसी भी मिल में कामबंदी का विरोध करती है। वर्तमान योजना एन टी सी समिति तथा सभी श्रमिक संघों के मध्य दो वर्ष तक विचार विमर्श होने के पश्चात् तैयार की गई थी। इस योजना में दो विशेष मुद्दे हैं जिनके अनुसार किसी मिल में काम बंदी नहीं होगी और न ही श्रमिकों की छंटनी की जाएगी। डी पी आर महाराष्ट्र (उत्तर) तथा महाराष्ट्र (दक्षिण) की सब्सिडेयरीज के साथ सम्बन्धित योजना के एक भाग को पहले ही बी आइ एफ आर द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

डब्ल्यू बी ए बी ओ, यू पी, एम पी, तथा गुजरात की सब्सिडेयरीज के साथ सम्बन्धित दूसरा भाग अभी भी लम्बित पड़ा है क्योंकि बी आइ एफ आर ने तत्कालीन कांग्रेस (इ) सरकार को उनके ऋणों को माफ कर देने अथवा उन्हें एक्विटी में परिवर्तित करने के लिये कहा था। कांग्रेस सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अत: इन सब्सिडेयरीज के ऊपर बी आइ एफ आर द्वारा जारी किये जाने वाले कामबंदी के नोटिस के खतरे की तलवार लटक रही है।

इसलिये वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों के पुनर्जीवन सम्बन्धी अपने सांझे न्यूनतम कार्यक्रम का अनुपालन करते हुए ऋणों की माफी के लिये तत्काल कदम उठाने होंगे ताकि बंगाल, यू पी, एम पी तथा गुजरात की इन चार सब्सिडेयरीज के अन्तर्गत चलने वाली एन टी सी की बीमार मिलों को वर्तमान योजना के अन्तर्गत पुनर्जीवित किया जा सके।

सी आइ टी यू सरकार द्वारा श्रमिक संघों के साथ विचार विमर्श किये बिना की जाने वाली किसी भी असुखद कार्रवाई का विरोध करती है।

□